

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1482
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

असम में भूजल में आर्सेनिक का स्तर

1482. श्री गौरव गोगोई:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के 19 जिलों में 0.01 मिलीग्राम/लीटर से अधिक आर्सेनिक का स्तर पाया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा प्रभावी शमन एवं उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार ने आर्सेनिक से प्रभावित उक्त क्षेत्रों में दुष्परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वास्थ्य प्रभाव आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा आर्सेनिक से प्रभावित होने के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने तथा सुरक्षित पेयजल प्रचलनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) भविष्य में असम में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक संदूषण को रोकने के लिए वचाराधीन दीर्घकालिक रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता आंकड़े तैयार करता है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार किए गए प्री-मॉनसून, 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, असम के 9 जिलों अर्थात् बारपेटा, गोलपाड़ा, गोलाघाट, कार्बी-आंगलोंग, कोकराझार, लखीमपुर, शिवसागर, नलबाड़ी और करीमगंज के अलग-अलग इलाकों में निर्धारित सीमा से अधिक भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी की सूचना मिली है।

जल राज्य का विषय होने के कारण गुणवत्ता पहलू सहित भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के रूप में असम सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

- सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है। भूजल गुणवत्ता पर ज्ञान के प्रसार में और तेजी लाने के लिए, सीजीडब्ल्यूबी ने अर्ध-वार्षिक भूजल गुणवत्ता बुलेटिन और पाक्षक अलर्ट जारी करता है ताकि सूचित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके।
- सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत मान चित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) के अंतर्गत भूजल में वषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी संदूषण मुक्त जलभृतों के दोहन के लिए नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं के निर्माण में राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।
- सीपीसीबी ने लघु उद्योगों के क्लस्टर के लिए साझा बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना; बहिस्त्राव की गुणवत्ता आदि के संबंध में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना के माध्यम से मुख्य बिंदु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है, जिसके मुख्य घटक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अपशिष्टों के निर्वहन के लिए उद्योग व शिफ्ट मानकों और सामान्य मानकों का विकास कर रहे हैं।
- भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के जल की आपूर्ति प्रदान की जा सके। जेजेएम के तहत, घरों में नल से जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित स्थानों में रहने वाली आबादी को 10% महत्व दिया जाता है।
- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक रूप से जागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

(ग): पीने के उद्देश्य के लिए आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं आदि का अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में लंबे समय तक उपयोग करने से स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आर्सेनिक के उद्भासन से त्वचा पर घाव, कैंसर, बच्चों में हृदवाहिका रोग और विकासात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

(घ): आर्सेनिक प्रभाव के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई उपाय शुरू किए गए हैं। सबसे पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा "भारत में आर्सेनिकोसिस का पता लगाने, रोकथाम और प्रबंधन" के लिए तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों और कार्यक्रम प्रबंधकों द्वारा उपयोग के लिए प्रभावित राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। इनका उपयोग चकत्सा अधिकारियों, पराचकत्सा कार्यकर्ताओं आदि जैसे फ़िल्ड कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाना है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइटों पर दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

रोग के लक्षणों और आर्सेनिकोसिस की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों के साथ सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी साझा की है। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों के प्रसार के लिए और आर्सेनिक जैसे वषैले तत्वों द्वारा संदूषण के मुद्दों सहित भूजल से संबंधित मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किया जाता है। अब तक सीजीडब्ल्यूबी ने देश भर में ऐसे 1518 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

जल जीवन मशन के तहत पेय जल की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए, "पेयजल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी फ्रेमवर्क" तैयार किया गया था और अक्टूबर 2021 में राज्यों को प्रसारित किया गया था। उपर्युक्त फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, फ़िल्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।

(ङ): भूजल का आर्सेनिक संदूषण मुख्यतः भू-जनित प्रकृति के रूप में जाना जाता है अर्थात् संदूषण अनुकूल परिस्थितियों में चट्टान और मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से भूजल में आर्सेनिक युक्त यौगकों के घुलने के माध्यम से होता है। इस समस्या के लिए सबसे अच्छा दीर्घकालिक उपाय दूषित स्रोतों की पहचान करने के लिए नियमित गुणवत्ता परीक्षण, आर्सेनिक सुरक्षित जलभृतों का दोहन और पीने के लिए वैकल्पिक स्रोतों, विशेष रूप से सतही जल स्रोतों आदि पर स्विच करना माना जाता है। इस दिशा में, जेजेएम-हर घर जल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जेजेएम के तहत संचयी प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह पाया गया है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2025 तक देश में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या 14,020 से घटकर 314 हो गई है। इन शेष बस्तियों को सामुदायिक जल शोधक संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल भी प्रदान किया गया है। जेजेएम पोर्टल के अनुसार, असम में 81% ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और जैसा कि सूचित किया गया है, आर्सेनिक से प्रभावित कोई भी बस्ती नहीं बची है।
